30 मई हिन्दी पत्रकारिता दिवस

हिन्दी पत्रकारिता दिवस : बदलते दौर में सच की तलाश

भारत में हर वर्ष 30 मई को हिन्दी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। यह दिन केवल एक औपचारिक उत्सव नहीं, बल्कि उस वैचारिक यात्रा का स्मरण है जिसने देश की चेतना को शब्द दिए। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से हिन्दी के प्रथम समाचार पत्र उदन्त मार्तण्ड का प्रकाशन शुरू किया था। उसी ऐतिहासिक क्षण ने हिन्दी पत्रकारिता की नींव रखी। तब से लेकर आज तक हिन्दी पत्रकारिता ने स्वतंत्रता आंदोलन, सामाजिक सुधार, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनसरोकारों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

लेकिन आज जब हिन्दी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, तब उत्सव के साथ कई गंभीर प्रश्न भी सामने खड़े दिखाई देते हैं। क्या पत्रकारिता अपने मूल उद्देश्य से भटक रही है? क्या बाजारवाद और तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने पत्रकारिता की आत्मा को कमजोर किया है? और सबसे बड़ी चिंता यह है कि भविष्य में हिन्दी पत्रकारिता किस दिशा में जाएगी? इन सवालों पर गंभीर समीक्षा और विश्लेषण की आवश्यकता है।

हिन्दी पत्रकारिता केवल समाचार देने का माध्यम नहीं रही, बल्कि यह भारतीय समाज की जागरूकता की धुरी रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिन्दी अखबारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जनमत तैयार किया। उस दौर में पत्रकारिता मिशन थी, व्यवसाय नहीं। पत्रकार जेल गए, आर्थिक संकट झेले, लेकिन सत्य और समाज के पक्ष में खड़े रहे।

गणेश शंकर विद्यार्थी, बाल गंगाधर तिलक और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे पत्रकारों ने कलम को सामाजिक परिवर्तन का हथियार बनाया। पत्रकारिता का उद्देश्य सत्ता से प्रश्न करना और जनता की आवाज़ बनना था।

उस समय समाचार पत्रों में भाषा की गंभीरता, विचारों की गहराई और समाज के प्रति उत्तरदायित्व दिखाई देता था। ग्रामीण भारत, किसानों, मजदूरों, शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता जैसे विषय पत्रकारिता के केंद्र में होते थे। यही कारण था कि हिन्दी पत्रकारिता ने समाज को जोड़ने का कार्य किया। समय के साथ पत्रकारिता का स्वरूप तेजी से बदला। तकनीक ने सूचना को तेज बना दिया। इंटरनेट, मोबाइल और सोशल मीडिया ने खबरों की दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। आज समाचार कुछ सेकंड में देश-दुनिया तक पहुंच जाता है। यह बदलाव सकारात्मक भी है, क्योंकि सूचना अब सीमित वर्ग तक नहीं बल्कि आम आदमी तक पहुंच रही है।

लेकिन इसी बदलाव के साथ पत्रकारिता में कई चिंताजनक प्रवृत्तियां भी बढ़ी हैं। आज खबरों की जगह 'टीआरपी' और 'व्यूज' ने ले ली है। कई मीडिया संस्थानों में पत्रकारिता जनहित की बजाय व्यापार का माध्यम बनती दिखाई देती है। सनसनी, बहसों का शोर, राजनीतिक ध्रुवीकरण और सोशल मीडिया की प्रतिस्पर्धा ने समाचारों की गंभीरता को प्रभावित किया है।

आज का दर्शक तेजी से बदल रहा है। उसे छोटी, तेज और आकर्षक सामग्री चाहिए। परिणामस्वरूप गहन विश्लेषण और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग कम होती जा रही है। टीवी चैनलों पर चीखती बहसें और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधूरी खबरें पत्रकारिता की विश्वसनीयता को चुनौती दे रही हैं।

सबसे बड़ी समस्या 'फेक न्यूज' की है। सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन के सूचनाएं वायरल हो जाती हैं। कई बार लोग समाचार और अफवाह में अंतर ही नहीं कर पाते। इससे समाज में भ्रम और तनाव बढ़ता है। पत्रकारिता का मूल आधार सत्य है, लेकिन जब सत्य की जगह जल्दबाजी ले लेती है, तब लोकतंत्र कमजोर होने लगता है।

हिन्दी पत्रकारिता के सामने भाषा का संकट भी गंभीर होता जा रहा है। पहले हिन्दी समाचारों में साहित्यिक सौंदर्य और भाषाई गरिमा दिखाई देती थी, लेकिन आज तेजी और प्रतिस्पर्धा में भाषा की शुद्धता और संवेदनशीलता कमजोर पड़ रही है। अंग्रेजी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग और सतही प्रस्तुति हिन्दी की आत्मा को प्रभावित कर रही है।

इसके साथ ही पत्रकारिता में मानवीय संवेदनाएं भी कम होती दिखाई देती हैं। दुर्घटनाओं, अपराधों और निजी दुखों को कई बार मनोरंजन की तरह प्रस्तुत किया जाता है। कैमरे की दौड़ में इंसानी पीड़ा पीछे छूट जाती है। यह स्थिति पत्रकारिता की नैतिकता पर प्रश्नचिह्न खड़ा करती है

भारत की बड़ी आबादी गांवों में रहती है, लेकिन मुख्यधारा की पत्रकारिता में ग्रामीण मुद्दे लगातार कम हो रहे हैं। किसानों की समस्याएं, जल संकट, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और स्थानीय विकास जैसे विषय अक्सर केवल बड़ी घटनाओं तक सीमित रह जाते हैं। ग्रामीण पत्रकार आज भी सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं। उन्हें न पर्याप्त सुरक्षा मिलती है और न ही आर्थिक स्थिरता। कई बार स्थानीय पत्रकार दबाव, धमकी और उपेक्षा के बीच अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं।

हिन्दी पत्रकारिता का वास्तविक भविष्य तभी मजबूत होगा जब गांवों की आवाज़ को केंद्र में रखा जाएगा।

डिजिटल मीडिया ने हिन्दी पत्रकारिता को नई ऊर्जा दी है। आज छोटे शहरों और गांवों के युवा भी मोबाइल पत्रकारिता के माध्यम से अपनी बात दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। यूट्यूब, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति के नए रास्ते खोले हैं।

लेकिन डिजिटल पत्रकारिता के सामने भी कई खतरे हैं। सबसे बड़ा खतरा 'सूचना की अति' है। हर व्यक्ति खबर देने लगा है, लेकिन हर कोई पत्रकारिता के मूल सिद्धांतों को नहीं समझता। बिना तथ्य जांचे सामग्री डाल देना समाज में भ्रम फैलाता है।

दूसरी चिंता कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई की है। आने वाले समय में समाचार लेखन, वीडियो प्रस्तुति और सामग्री निर्माण में एआई का उपयोग तेजी से बढ़ेगा। इससे पत्रकारिता आसान तो होगी, लेकिन मानवीय संवेदनशीलता और मौलिकता पर असर पड़ सकता है। यदि पत्रकार केवल तकनीक पर निर्भर हो जाएंगे तो पत्रकारिता मशीनों की सूचना बनकर रह जाएगी।

हिन्दी पत्रकारिता के भविष्य की सबसे बड़ी चिंता उसकी विश्वसनीयता है। यदि जनता का विश्वास मीडिया से कम हो गया तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कमजोर पड़ जाएगा। पत्रकारिता का अर्थ केवल खबर दिखाना नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा देना भी है।

आज युवा पीढ़ी तेजी से सोशल मीडिया की ओर बढ़ रही है। यदि मुख्यधारा की पत्रकारिता निष्पक्षता और जनविश्वास खोती रही, तो लोग वैकल्पिक मंचों पर निर्भर हो जाएंगे, जहां सत्य और असत्य का अंतर और अधिक धुंधला हो सकता है।

इसके अलावा पत्रकारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति भी चिंता का विषय है। छोटे संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों को कम वेतन, असुरक्षा और राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। ऐसे माहौल में स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता करना कठिन होता जा रहा है।

हिन्दी पत्रकारिता को अपने मूल मूल्यों की ओर लौटना होगा। सत्य, निष्पक्षता, संवेदनशीलता और जनहित को फिर से केंद्र में लाना होगा। पत्रकारिता संस्थानों को केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में काम करना चाहिए।

पत्रकारिता शिक्षा को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। युवा पत्रकारों को तकनीक के साथ नैतिकता और तथ्य जांच का प्रशिक्षण देना जरूरी है। मीडिया संस्थानों को ग्रामीण पत्रकारिता, खोजी पत्रकारिता और सामाजिक मुद्दों पर गंभीर कार्य को बढ़ावा देना चाहिए।

साथ ही पाठकों और दर्शकों की भी जिम्मेदारी है कि वे सनसनी से अधिक सत्य को महत्व दें। समाज जैसा देखना चाहता है, मीडिया वैसा ही बनने लगता है। इसलिए जागरूक नागरिक ही स्वस्थ पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं।

हिन्दी पत्रकारिता दिवस केवल अतीत का गौरव गान करने का अवसर नहीं, बल्कि आत्ममंथन का दिन भी है। हिन्दी पत्रकारिता ने देश को जागरूक बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, लेकिन वर्तमान दौर में उसके सामने विश्वसनीयता, नैतिकता, बाजारवाद और तकनीकी चुनौतियों का बड़ा संकट खड़ा है।

भविष्य की चिंता इसलिए आवश्यक है क्योंकि पत्रकारिता केवल उद्योग नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है। यदि पत्रकारिता सच बोलने का साहस खो देगी तो समाज दिशाहीन हो जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हिन्दी पत्रकारिता फिर से जनसरोकारों, मानवीय मूल्यों और सत्य की राह पर मजबूती से खड़ी हो। तभी हिन्दी पत्रकारिता दिवस का वास्तविक अर्थ सार्थक होगा।

एडवोकेट, जयदेव राठी

घुसपैठिए या दीमक

अवैध घुसपैठ राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक ढांचे के लिए खतरा बन रही है लेकिन, वोटबैंक की राजनीति के चलते कुछ नेताओं ने घुसपैठियों को खुली छूट दे रखी थी। इन अवैध प्रवासियों के कारण आबादी में होने वाले बदलावों के कारण शासन व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाओं, सीमा सुरक्षा और सामाजिक ताने-बाने पर पड़ने वाले असर ने देश को महंगाई और जनसंख्या के मामले में बर्बाद करके रख दिया है। अगर देश के एक-एक गाँव और शहर से चुन-चुनकर बांग्लादेश, रोहिंगीया, नेपाल, पाकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और म्यांमार जहाँ कहीं से भी आकर भारत को धर्मशाला समझकर डेरा डाले पड़े घुसपैठियों को निकाल दिया जाए तो भारत की भूमि हल्का महसूस करते राहत की साँस लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। घुसपैठिए हमारे देश की जनता के अधिकारों पर कब्ज़ा जमाकर बैठे है, यह एक जटिल और बहुचर्चित मुद्दा है, जिसके संभावित परिणामों को अलग-अलग प्रमुख क्षेत्रों में समझा जाए तो आर्थिक और ढांचागत प्रभावसंसाधनों पर दबाव कम पडेगा साथ ही सरकारी सब्सिडी, खाद्यान्न वितरण और आवास योजनाओं पर पड़ने वाला अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगा। रोज़गार के अवसर: असंगठित क्षेत्र और सस्ते श्रम बाज़ार में स्थानीय कामगारों के लिए प्रतिस्पर्धा घटेगी, जिससे वेतन स्तर में सुधार हो सकता है।

अल्पकालिक आर्थिक व्यवधान की बात करें तो निर्माण, कपड़ा, और कृषि जैसे क्षेत्रों में जो सस्ते प्रवासी श्रमिकों पर अत्यधिक निर्भर हैं, अचानक से कामगारों की कमी और उत्पादन लागत में वृद्धि देखने को मिल सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्थाअपराध दर में कमी भी कमी आएगी ये सबसे अहम बात है। अवैध गतिविधियों, जैसे- जाली मुद्रा नशीली दवाओं की तस्करी, बच्चियों पर बलात्कार और मानव तस्करी से जुड़े तमाम नेटवर्कों में कमी आने की संभावना है।तदुपरांत देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध प्रवास से जुड़ी संवेदनशील जनसांख्यिकीय और सुरक्षा चुनौतियों का समाधान होगा और देश विरोधी गतिविधियाँ भी कम होगी। सामाजिक और प्रशासनिक ढांचासामाजिक सेवाओं पर जरूरत से ज्यादा बोझ पड़ रहा है उसमें भी फ़र्क़ पड़ेगा साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं, स्कूलों और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर स्थानीय आबादी का दबाव कम होगा।

कानूनी प्रक्रिया में हल्का बदलाव करते सभी अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस भेजने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर जैसी प्रक्रियाओं की आवश्यकता है, जिसमें भारी प्रशासनिक और न्यायिक संसाधन लगेंगे लेकिन देशहित में यह निर्णय सर्वोपरि साबित होगा। कूटनीतिक और मानवाधिकार संबंधी चुनौतियां अंतरराष्ट्रीय संबंध जिन देशों के नागरिकों को वापस भेजा जाएगा, उन पड़ोसी देशों के साथ राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है लेकिन देश की सुरक्षा हेतु सरकार इतनी तो हैंडलिंग कर सकती है। इस प्रक्रिया के दौरान मानवाधिकार संगठनों की ओर से कानूनी और मानवीय आपत्तियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब भारत को घुसपैठियों से आज़ाद करवाना बेहद जरूरी हो गया है क्योंकि घुसपैठिए देश को दीमक की तरह खा रहे है। बंग्लादेशी हर जिल्ले, हर राज्य में छुपे बैठे हैं। जमशेदपुर में भी हजारो बंग्लादेशी है जो मुर्शिदाबाद का नाम लेकर भारत में रह रहे है। बेकरी में बंग्लादेशी, राजमिस्त्री, पंचर वाला, सब्जी वाला, ट्रेलर सभी बंग्लादेशी प्रचूर मात्रा में भिन्न भिन्न जगहो में अवैध रूप से रह रहे है। बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में भरे पड़े है। बिरियानी, पंचर, कपड़े जैसी दुकानें खोलकर पूरी दादा गिरी के साथ रहते है। लेकिन मौजूदा सरकार अब जागी है ये बड़ी खुशी की बात है। खदेड रही है घुसपैठियों को। लेकिन याद रहे देश से निकालते वक्त घुसपैठिए को तभी जाने दिया जाए जब वो बताए उनको यहाँ लाने वाले का नाम। नकली आधार कार्ड, चुनाव कार्ड, पैनकार्ड वगैरह दस्तावेज बनाकर देने वाले के नाम। फिर इनकी जुबानी को कोर्ट में पेश करके उन दलाल देश द्रोहियों पर भी कार्रवाई की जाए तभी देश के हालात में सुधार ला सकते है।

भावना ठाकर 'भावु' बेंगलोर

बढ़ती लागत पर भारी पड़ा भारतीय लघु उद्योगों का जज़्बा ; सीपीए ऑस्ट्रेलिया सर्वेक्षण

नई दिल्ली। सीपीए ऑस्ट्रेलिया के एशिया-प्रशांत लघु उद्योग सर्वेक्षण 2025/26 के अनुसार, भारतीय लघु उद्योगों ने वर्ष 2025 में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 2019 के बाद से यह इनका सबसे दमदार प्रदर्शन रहा है। हालांकि, खर्चों के बढ़ते बोझ ने भविष्य की राह में कुछ चुनौतियां जरूर पेश की हैं, लेकिन 2026 में विकास को लेकर इन कारोबारियों का हौसला बुलंद है। सर्वेक्षण के आंकड़े गवाही देते हैं कि बीते साल 80 प्रतिशत भारतीय लघु उद्योगों ने तरक्की की राह पकड़ी, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 63 प्रतिशत के औसत के मुकाबले काफी आगे है। भविष्य पर नजर डालें तो, 87 प्रतिशत कारोबारियों को 2026 में अपना व्यवसाय और बढ़ने की उम्मीद है, जबकि 84 प्रतिशत अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर आश्वस्त हैं। अपने पड़ोसी देशों को पीछे छोड़ते हुए, भारत इस क्षेत्र के सबसे सकारात्मक लघु उद्योग बाजारों के रूप में उभरकर सामने आया है। वर्ष 2025 में मिली इस बड़ी कामयाबी के पीछे मुख्य रूप से बेहतर ग्राहक सेवा, कुशल प्रबंधन और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल का बड़ा हाथ रहा है। मजबूत आत्मविश्वास के बावजूद, खर्चों का बढ़ता बोझ विकास की राह में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। सर्वेक्षण के अनुसार, 42 प्रतिशत प्रतिभागियों ने बढ़ती लागत को 2025 की सबसे बड़ी चुनौती माना, जिसमें कच्चे माल की कीमतों ने लगातार तीसरे साल कारोबार को सबसे ज्यादा चोट पहुँचाई है। सीपीए ऑस्ट्रेलिया के फ़ेलो (एफसीपीए) और भारत में सीपीए ऑस्ट्रेलिया के प्रवक्ता, श्री अनिकेत तलाटी, ने कहा कि भारतीय एमएसएमई ने मजबूत घरेलू मांग के सहारे विस्तार की स्पष्ट तैयारी और आत्मविश्वास दिखाया है। उन्होंने कहा, 'व्यवस्थित और विकास को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियों के साथ-साथ मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए नए निर्यात बाजारों तक पहुंच बढ़ने से भारतीय एमएसएमई को आगे बढ़ने में मदद मिली है। शुल्कों के प्रभाव को कम करने में भी इन समझौतों की अहम भूमिका रही है। पिछले वर्ष भारतीय एमएसएमई ने मजबूत प्रदर्शन और आत्मविश्वास दिखाया, और 2026 में भी वे बड़े विस्तार की योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं।' हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कारोबारी माहौल अब पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। उन्होंने कहा, 'मार्च के बाद से बढ़ी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने केवल भारत ही नहीं, बल्कि कई देशों के कारोबारी माहौल को प्रभावित किया है। ऊर्जा और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ सकता है।' श्री अनिकेत तलाटी ने अपनी बात रखते हुए कहा, ;इसके साथ ही, रुपये की कीमत

में उतार-चढ़ाव निर्यात से होने वाले मुनाफे को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है। बेहतरीन गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी कीमतों वाले भारतीय उत्पाद आज भी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। हाल ही में हुए नए मुक्त व्यापार समझौतों ने निर्यात की संभावनाओं को लेकर भरोसे को और भी पुख्ता किया है। कुल मिलाकर, मैं भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के भविष्य को लेकर काफी सकारात्मक हूँ। हालांकि, आने वाले समय में विकास और लाभ की रफ्तार बनाए रखने के लिए व्यवसायों को बेहतर योजना, लागत और जोखिम के प्रभावी प्रबंधन, तथा नवीकरणीय ऊर्जा और वैकल्पिक कच्चे माल में निवेश पर विशेष ध्यान देना होगा।

50 प्रतिशत से अधिक लघु उद्योगों ने दिए नए रोजगार: भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग देश में रोजगार बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस क्षेत्र को खास तौर पर युवा उद्यमियों की नई पीढ़ी से नई ऊर्जा मिल रही है, जो कारोबार के तरीके बदलने और विकास को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सर्वेक्षण के मुताबिक, वर्ष 2025 में 52 प्रतिशत भारतीय लघु उद्योगों ने अपने यहाँ कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई। वहीं, 69 प्रतिशत उद्योग 2026 में नई भर्तियाँ करने की योजना बना रहे हैं। यह आंकड़ा कई अन्य एशियाई देशों की तुलना में काफी बेहतर है। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि भारत के 56 प्रतिशत लघु उद्योग मालिकों की उम्र 40 वर्ष से कम है, जबकि एशिया-प्रशांत क्षेत्र का औसत 38 प्रतिशत है। युवाओं की यह मजबूत भागीदारी भारत के लिए बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। इससे डिजिटल तकनीक को अपनाने, नए विचारों पर काम करने और आधुनिक कारोबारी मॉडल विकसित करने की रफ्तार तेज हुई है। यही वजह है कि भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग अपने लंबे समय में स्थायी और लंबे समय तक विकास करने की मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं।

डिजिटल भुगतान और ई-कॉमर्स की दौड़ में सबसे आगे : पूरे क्षेत्र में डिजिटल बदलाव की लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2025 में 89 प्रतिशत भारतीय लघु उद्योगों ने अपनी कुल आय का 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा डिजिटल भुगतान माध्यमों से हासिल किया, जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे अधिक है। इसके साथ ही, 74 प्रतिशत व्यवसायों ने अपनी कमाई का 10 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा ई-कॉमर्स के जरिए अर्जित किया। सर्वेक्षण में यह भी सामने आया कि हर 10 में से 9 उद्योग अपने कारोबार से जुड़े कामों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारतीय लघु उद्योगों के दैनिक कामकाज में डिजिटल तकनीकों और ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग अब तेजी से सामान्य और जरूरी हिस्सा बन चुका है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में बढ़ा निवेश: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में भी भारतीय लघु उद्योगों का निवेश तेजी से बढ़ा है। वर्ष 2025 में एआई में निवेश करने वाले भारतीय लघु उद्योगों का अनुपात 26 प्रतिशत से बढ़कर 36 प्रतिशत हो गया, जिससे यह सबसे प्रमुख तकनीकी निवेश के रूप में उभरा। इसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग में 35 प्रतिशत और ग्राहक संबंध प्रबंधन प्रणालियों में 30 प्रतिशत निवेश दर्ज किया गया। खास बात यह रही कि 41 प्रतिशत उद्योगों ने कारोबारी सलाह और निर्णय लेने के लिए एआई उपकरणों का इस्तेमाल किया, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 25 प्रतिशत था। कई व्यवसायों का कहना है कि तकनीक में किए गए निवेश से पिछले 12 महीनों में उनके मुनाफे में सुधार हुआ है, जो यह दिखाता है कि डिजिटल तकनीक अब भारतीय एमएसएमई के विकास का अहम आधार बन चुकी है। यही बदलाव नवाचार को भी नई रफ्तार दे रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार, 44 प्रतिशत भारतीय एमएसएमई वर्ष 2026 में नए उत्पाद या सेवाएँ लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, जो सर्वेक्षण के औसत 29 प्रतिशत से काफी अधिक है।